Amendment of Consumer Protection Act

*199. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether there is a persistent demand from various quarters to amend the Consumer Protection Act of 1986;

(b) whether Government have received a number of representations in this regard;

(c) if so, the reaction of Government thereto; and

(d) the steps Government propose to take to make Consumer Protection Act more effective?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAO BIRENDRA SINGH): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The matter was considered in the Central Consumer Protection Council and on its recommendations a Working Group has been constituted *vide* order dated 7.1.1991 to consider these suggestions. The Working Group has been asked to give its Report within four months.

Agricultural education in the country

*200. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:
SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of Agricultural Universities and Agricultural Colleges in the country;

(b) whether Government propose to make agricultural education as mass education in the country; and

(c) if so, what are the future plans of agricultural education in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHANDBHAI SHAH): (a) Sir, There are 26 State Agricultural Universities and 95 Agricultural Colleges in the country.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

गांव को सड़कों के साथ जोड़ना

@1100 डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अधिकांश गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1990 के अंत तक संपूर्ण देश में कुल कितने प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़े हुए थे ;

(ग) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए कोई समय-बद्ध योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार इस दिशा में कब तक निर्णय करेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह): (क) व (ख) जी नहीं। यह अनुमान लगाया गया है कि देश भर में 1500 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले 90 प्रतिशत गांवों, 1000 से 1500 तक की आबादी वाले 68 प्रतिशत गांवों और 1000 से कम की जनसंख्या वाले 36 प्रतिशत गांवों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सम्पर्क सड़कों से जोड़ा गया है। 1990 के अंत तक सम्पर्क सड़कों से जोड़े गए गांव अनुमानतः लगभग 50 प्रतिशत है।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न सं० 451, 27 फरवरी, 1991 से स्थानान्तरित।

(ग) व (घ) : योजना आयोग राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रत्येक योजना अवधि के दौरान कवरेज के लिए मानदंड निर्धारित करता है तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जाती है । गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए जिस समय-सीमा और मानदंडों की परिकल्पना की गई थी, उन्हें पर्वतीय, आदिवासी, तटीय तथा मरुभूमि क्षेत्रों के लिए और अधिक उदार मानदंडों के साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाए जाने हेतु जारी रखा गया था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

1. पर्वतीय, आदिवासी, तटीय तथा मरुभूमि क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए मानदंड

(क) 1500 की आबादी वाले 100 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ना ।

(ख) 1000 से 1500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ना ।

2. पर्वतीय क्षेत्र

(क) 500 से अधिक की जनसंख्या वाले 100 प्रतिशत गांवो को 10 वर्ष की अवधि के दौरान सड़कों से जोड़ना ।

(ख) 200 से 500 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 10 वर्ष की अवधि के दौरान सड़कों से जोड़ना ।

3. आदिवासी, तटीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्र :

3. आदिवासी, तटीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्र

(क) 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले 100 प्रतिशत गांवों को 10 वर्ष की समयावधि के दौरान सड़कों से जोड़ना ।

(ख) 500 से 1000 तक की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 10 वर्ष की समयावधि के दौरान सड़कों से जोड़ना ।

तथापि, संसाधनों की कमी की वजह से निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों में अभी भी अंतर है ।

Target of foodgrains production

1101. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the target of foodgrains production fixed for the Seventh Plan period; and

(b) the results achieved, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JAYANTILAL VIRCHANDBHAI SHAH): (a) A target of 175 million tonnes of foodgrains production was fixed for 1989-90, the terminal year of Seventh Five Year Plan.

(b) A *Statement* giving actual production of foodgrains in different states during 1989-90 is enclosed.

Statement

Estimate of production of Total Food Grains during 1989-90

(In Thousand Tonnes)

State	Production 1989-90
Andhra Pradesh . . .	12629·9
Arunachal Pradesh . . .	207·6
Assam . . .	2951·1
Bihar	11844·0
Goa	168·1
Gujarat	4787.8
Haryana . .	8651·6
Himachal Pradesh . . .	1419·9